सरकार तक पहुंचे नौकरी घोटाले के तार, क्या इसीलिए कतरा रहे हैं मुख्यमंत्री न्यायिक जांच से: सुरजेवाला

-अगर मुख्यमंत्री पाक साफ होने का दावा कर रहे हैं तो हाईकोर्ट से क्यों नहीं करवा रहे नौकरी घोटाले की जांच

-नौकरी घोटाला रैकेट की सही जांच हो, तो होंगे बड़े बड़े चेहरे बेनकाब

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि नौकरी घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों से हो रहे कथित खुलासों से साफ हो गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में नौकरियों की बोली लगाने वाले रैकेट के हाथ बेहद लंबे थे और कमीशन के चेयरमैन, सदस्यों, सचिव के अलावा पुलिस, स्वास्थ्य और वित्त विभाग से भी जुड़े थे। यह केवल पूरी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है और इस मामले में अभी असली खुलासा होना बाकी है। अगर इस नौकरी घोटाले की निष्पक्षता से जांच हो तो, बड़े-बड़े चेहरे बेनकाब होंगे।

श्री सुरजेवाला ने आज यहां जारी एक ब्यान में कहा कि अब ये साफ होता जा रहा है कि नौकरी घोटाले की कई परतें अभी सामने आनी बाकी हैं और असली सरगना अभी भी पर्दे के पीछे छिपे हैं। उन्होंने कहा कि साफ बात है कि हरियाणा पुलिस का सीएम फ्लाईंग जत्था अपने मुखिया या मुख्यमंत्री कार्यालय तथा सरकार से जुड़े तारों का खुलासा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में पाक साफ हैं तो उन्हें हाईकोर्ट के दो सीटिंग जजों से जांच करवाने से गुरेज क्यों है।

नौकरी घोटाले की जांच से जुड़े समाचारों का हवाला देते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि उम्मीदवारों को इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर सलेक्शन करवाई गई, जबकि साक्षात्कार के उम्मीदवारों को नंबर बिना आयोग के चेयरमैन, सदस्यों व सचिव की मिलीभगत के बिना नहीं बढ़ाए जा सकते। ऐसे में आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा दफ्तर में कथित रूप से कार्यरत रहे पुनीत सैनी को नौकरी घोटाले का सरगना और

आयोग के चेयरमैन का खासमखास बताया जा रहा है। जिस प्रकार से यह बताया गया है कि पुनीत सैनी वेतन भी नहीं ले रहे थे, ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती और पर्दे के पीछे छिपे उनके संरक्षकों की पूरी जांच पड़ताल होना आवश्यक है, जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम नहीं हैं।

श्री सुरजेवाला ने जांच प्रक्रिया पर सीधा प्रश्न उठाते हुए पूछा कि अभी तक कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों पर एफआईआर करके गिरफ्तार करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई गई है। घोटाले से जुड़े पर्दे के पीछे छिपे आरोपी आयोग कार्यालय में अपने आप को बचाने के लिए रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन सरकार केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि न्यायिक जांच नहीं करवाते तो इसका मतलब साफ़ होगा कि वे घोटाले के आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक हक नहीं रह गया है। ऐसे में उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।